लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1 से 15 जनवरी 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-9

"इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं।
: शिवानी

आयुष चिकित्सा पर्यटन की ओर बढ़ते कदम 3

किसानों के साथ मिलकर शहद का कारोबार करेगा हैफेड 5

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 8

नव वर्ष

सुशासन के संकल्प से बदलती तस्वीर

विशेष प्रतिनिधि

'सबका साथ-सबका विकास' मूलमंत्र को लेकर चली वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है। प्रदेश की जनता ने गठबंधन सरकार से जो उम्मीदें लगाई थीं, उन्हीं के अनुरूप काम हो रहा है। बिना किसी भेदभाव के समान विकास सरकार की मुख्य उपलब्धि है। यह संभव हुआ सुशासन से। सुशासन का संकल्प साफ नीयत का प्रतिमान है। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था से प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति जो भरोसा कायम हुआ है वह शायद पहले कभी नहीं देखा गया।

राज्य में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। कई नई योजनाओं की आधारशिलाएं रखी जा चुकी हैं तथा उनके पूरा होने का समय निर्धारित किया गया है। प्रशासनिक एवं ढांचागत स्तर की अनेक योजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश के लोगों का जीवन और सहज एवं अनुशासित होगा। आम जनमानस सरकारी व्यवस्था में पैर जमा चुके भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार से तंग था। वर्तमान में सरकारी कार्यालयों के कामकाज को जिस अनुशासित व्यवस्था के तहत ढाला जा रहा है उससे राज्य सरकार की 'जीरो टालरेंस' की नीति और मजबूत होगी।

डिजिटल होते गांव

'ग्राम दर्शन' पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है। इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा, गांव की पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची उपलब्ध होगी। गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने के लिए 'डिजिटल मैप' का शुभारम्भ किया गया है। इससे गांव की सम्पत्ति को विशेष पहचान के साथ-साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक व जमीन की खरीद-फरोख्त व ऋण लेने का अधिकार मिलेगा। प्रदेश के 114 गांव 'डिजिटल गांव' बन चुके हैं, अब एक क्लिक पर गांव के लोगों को सरकार की सैकड़ों योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।

बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत

'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' के तहत पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल व रेवाड़ी ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। योजना के तहत 5080 गांव शामिल हैं। प्रसारण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 26 नए सब-स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा 64 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई है। 415 करोड़ रुपए की लागत से 399 किलोमीटर लंबी प्रसारण लाइनें जोड़ी गई हैं। इतना ही नहीं प्रदेश में 12 हज़ार 442 नये ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं तथा एक लाख 29 हज़ार से ज़्यादा नये कनेक्शन दिये गए हैं। उपभोक्ताओं की मांग पर 96 करोड़ रुपए की लागत से कॉलोनियों, तालाबों तथा स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2539 लाइनों की शिफ्ट किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के नागरिक अस्पतालों को 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तरों का किया गया है। कोरियावास (महेन्द्रगढ़) में 598 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है तथा जींद में 664 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनके अतिरिक्त भिवानी और गुरुग्राम में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सिरसा, यमुनानगर तथा कैथल में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंज़ूरी हो चुकी है।

उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा

शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जितना कार्य गत छह वर्ष में हुआ है वह पहले नहीं हुआ। संबंधित योजनाओं का परिणाम यह है कि स्कूलों में न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार हुआ है बल्कि राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। 'हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा' की मान्यता 5 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 वर्ष की गई है। छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर महीने छह सैनेटरी पैड का पैकेट मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है जिससे 6 लाख 83 हज़ार छात्राएं लाभान्वित होंगी। राजकीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान किया गया है। छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 1000 प्ले स्कूल खोले जा रहे हैं।

सबको मिले रोज़गार

'बिन पर्ची बिन खर्ची' की रीति को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने गत वर्ष योग्यता के आधार पर 8,543 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। इनमें सबसे बड़ी क्लर्कों की भर्ती है। सभी नौकरियों में पारदर्शिता बरते जाने को लेकर प्रदेश का युवा वर्ग व अभिभावक खुश हैं। छह वर्ष में कुल मिलाकर 77,543 सरकारी नौकरियां दी गई है। इनके अलावा 349 रोज़गार मेले आयोजित हुए तथा कौशल विकास के जिनके ज़रिए 14,373 युवाओं को रोज़गार मिला। बेरोज़गारी भत्ता योजना' के तहत 12वीं, स्नातक तथा स्नातकोत्तर लगभग 18 हज़ार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

औद्योगिक विकास

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में गत एक वर्ष में 176.69 करोड़ रुपये के निवेश से 23 बड़े एवं मध्यम उद्योग लगे तथा इनमें 1315 लोगों को रोज़गार मिला। इसके अतिरिक्त 2016 करोड़ रुपये के निवेश से 14,804 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे तथा इनमें 94,261 लोगों को रोज़गार मिला है।

प्रदेश में निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने और युवाओं को विदेशों में रोज़गार में मदद करने के लिए 'विदेश सहयोग विभाग' गठित किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'एम.एस.एम.ई. विभाग' गठित किया है।

सुशासन के लिए कुछ अहम पहल

वर्ष 2021 को 'सुशासन परिणाम वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा। 'सुशासन संकल्प वर्ष 2020' के दौरान सुशासन के लिए किए गए विभिन्न आईटी सुधारों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रिय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने गत सप्ताह एक विशेष कार्यक्रम में सुशासन सुधार पर प्रकाशित 'सुशासन संकल्प पत्रिका' जारी की। कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में विभिन्न जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर लगभग 150 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया।

बागवानी बीमा योजना

बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की। इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुक्सान की भरपाई की जाएगी। योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्ज़ियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिण्डी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, मूली), दो मसाले (हल्दी, लहसुन) और चार फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) हैं।

शिक्षा ऋण सुविधा

हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की घोषणा की। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चतर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि वे चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें। वित्त विभाग द्वारा सृजित किए जा रहे कैडिट गारंटी निधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

आवेदन के लिए एक बार पंजीकरण

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इसके तहत, सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को एक जनवरी, 2021 से अलग पद के लिए अलग भुगतान नहीं करना होगा। आवेदक को एक बार पंजीकरण करना होगा और तीन साल में एक बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

सीएलयू ऑनलाइन

एक जनवरी, 2021 से सभी भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) ऑनलाइन दिए जाएंगे। नागरिक को कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा और यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद सीएलयू की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी।

निःशुल्क पासपोर्ट

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना के तहत पांच विद्यार्थियों को पासपोर्ट वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा विदेशों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के बारे जागरूक करना है।

24 घंटे बिजली आपूर्ति

'स्वामित्व योजना' के तहत, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 81 गांवों के 5,437 लाभार्थियों को स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) वितरित की। मुख्यमंत्री ने 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' के तहत प्रदेश के 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की घोषणा की। इससे अब इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गांवों की संख्या 5,080 हो जाएगी।

संपादकीय

पटरी पर लौटता जीवन

वर्ष 2020 ने जहां हमारी सामाजिकता, आर्थिकता विकास की गति और व्यवसायिकता पर गहरी खरोंचें छोड़ीं, वहां नए वर्ष के लिए अनेक सुखद व उत्साहवर्द्धक संदेश भी छोड़े हैं।

बीते वर्ष ने हमें नए वर्ष में विपरीत परिस्थितियों से अनवरत जूझने की प्रेरणा दी। 'दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी' और थोड़े-थोड़े अन्तराल के बाद हाथ धोते रहना एवं स्वच्छता बनाए रहना 'ऑन लाइन'। हम कहां थे अभ्यस्त इस जीवनशैली के। 'ऑन लाइन' शिक्षा, 'आन लाइन बैंकिंग', 'ऑन लाइन' मुशायरे, कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां, उद्घाटन एवं अध्यक्षीय भाषण, अब सब 'आन लाइन' चल रहा है। महत्वपूर्ण मंत्रिमण्डलीय बैठकें व महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील फैसले भी 'आन लाइन' होने लगे हैं।

हमें पहली बार महसूस हुआ है कि शादी-ब्याह व अन्य समारोहों पर अनाप शनाप खर्च से बखूबी बचा जा सकता है। यहां तक आकर्षक डिज़ाइनों वाले निमंत्रण पत्र भी 'ऑन लाइन' चल रहे हैं।

लेकिन बीते वर्ष ने हमें यह भी बताया है कि अनेक लक्ष्मण रेखाओं के बावजूद हमें पूरे परिवेश की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। चाहे सफ़ाईकर्मी हों या चिकित्साकर्मी या सुरक्षा कर्मी या पत्रकार या फिर सीमाओं पर विपरीत मौसम में भी मुस्तैद सैन्य कर्मी या फिर प्रयोगशालाओं में अपने शोर्ध-कार्य में कार्यरत वैज्ञानिक, सभी शारीरिक रूप में अपनी सि यता बनाए रहे हैं। खेतों में काम, सशरीर चल रहा है। बाज़ारों में कुछ अंतराल के बाद फिर से चहलपहल आरंभ हो गई है। न्यायपालिका भी 'ऑनलाइन' पद्धति पर काम करने लगी है। कार्यपालिका में भी पहले से कहीं ज्यादा जागरुकता आई है।

अब नव वर्ष 2021 में हम किसी भी प्राकृतिक आपदा से बेहतर ढंग से जूझने के लिए तैयार हैं। हम एक-दूसरे की मदद के तौर-तरीके भी सीखने लगे हैं और यह सुनिश्चित बनाने लगे हैं कि आसपास कोई भी अन्न, दवा, वस्त्र और छत के बिना न रहे। बसों, रेलों में यात्रा का तौर-तरीका भी हमने सीख लिया है। बहुत कुछ सीखा है नववर्ष के लिए लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना शेष भी है। अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष का 'ऑन लाइन' तौर तरीका भी शायद हम धीरे-धीरे सीख जाएंगे।

लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जीवन की गुणवत्ता में भ्रष्टाचार के कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा। भारत ही नहीं, विश्व के स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ना बहुत महंगा सिद्ध हुआ है और इसे दूर करने के लिए व्यापक प्रयास ज़रूरी हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रकाशन में ऐसे अध्ययनों की जानकारी दी गई है जो इस बढ़ती समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं। इन अध्ययनों में बताया गया कि 0-5 वर्ष आयु के एक लाख चालीस हज़ार बच्चों की मौत में भ्रष्टाचार की प्रमुख या आंशिक भूमिका है। जिन देशों में भ्रष्टाचार अधिक है, उनकी तुलना कम भ्रष्टाचार वाले देशों से की जाए तो पहली श्रेणी में बाल मृत्यु दर लगभग दो गुना अधिक है। भ्रष्टाचार के कारण विश्व स्तर पर एक ही वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में 455 अरब डालर की क्षति होती है, जबकि एक अन्य अध्ययन में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इस क्षति को 100 से 170 अरब डालर के बीच आंका गया है।

हमें इस रोग से बचना होगा, तभी हम नव वर्ष की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होंगे।

- डा. चंद्र त्रिखा

मंत्रिमंडल की ओर से कई परियोजनाओं को हरी झंडी

हरियाणा सचिवालय में बुधवार को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने की। बैठक में कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एचसीएमएस-ग्रुप ए) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर निकालकर इन पदों की 25 प्रतिशत सीधी भर्ती उसी विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई जिसने चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की थी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 74 से अधिक रिक्त पदों को 25 प्रतिशत कोटा के समक्ष सीधी भर्ती द्वारा तत्काल भरा जाना है।

होम्यपैथी कालेज के लिए जमीन

नगर परिषद, अम्बाला सदर की 61 कनाल और 13 मरला भूमि गांव चांदपुरा, जिला अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु 44 लाख रुपये प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर रेट तथा 120 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

योग आयोग

हरियाणा सरकार ने योग के बारे में जागरूकता, प्रसार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने का निर्णय लिया है ताकि यह बचपन से ही जीवन का हिस्सा बन सके।

इथेनॉल संयंत्र

करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी संयंत्र और इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। हरको बैंक ने इन तीनों परियोजनाओं के लिए 235.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया है।

मानेसर निगम में 29 गांव

गुरुग्राम में नए नगर निगम, मानेसर का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें साथ लगते 29 गांवों को शामिल किया जाएगा। नवसृजित नगर निगम मानेसर की सीमा में शामिल किए जाने वाले 29 गाँवों में मानेसर (ग्रामीण एवं शहरी), कासन, खोह, नाहरपुर कासन, नवादा, फतेहपुर, ढाणा, बास कूसला, बास हरिया, कांकरोला, भांगरोला, ढोरका, वजीरपुर, बढ़ा, सिकंदरपुर रामपुर (गांव शिकोहपुर की राजस्व सम्पदा में स्थित), शिकोहपुर, नखड़ोला, बार-गुज्जर, नौरंगपुर, मेवका, हयातपुर, सहरावन, नैनवाल, कुकड़ोला, झुंड सराय (वीरान), झुंड सराय(आबाद), फाजलवास, गोपालपुर और गढ़ी-हरसरू शामिल होंगे।

दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी

रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। आरआरटीएस के दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर की कुल लंबाई 103.02 किलोमीटर है और इसमें दिल्ली में छह और हरियाणा में 11 स्टेशनों सहित कुल 17 स्टेशन होंगे।

कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर

हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) विधेयक, 2020 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए समान कार्यकाल के लिए स्वीकृति दी गई है।

राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार

'डिजिटल हरियाणा' के विज़न को साकार करने के लिए सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने दस राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। विजेताओं को ये पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए।

'अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता और टीम के सदस्य श्री दीपक बंसल डीडीजी-सह-एसआईओ, श्री आलोक श्रीवास्तव वैज्ञानिक, श्री संदीप मोदगिल वैज्ञानिक, श्री रमनदीप कौशल और श्री आशुतोष द्विवेदी को सम्मानित किया गया।

सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान में तेज़ी और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम ईआरपी सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक पी.सी. मीणा व विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खंगवाल और प्रदीप कौशल सीनियर तकनीकी निदेशक एनआईसी को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

विविधिकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, महानिदेशक, बागवानी डॉ. अर्जुन सिंह सैनी और उनकी टीम के सदस्य डॉ. रणबीर सिंह संयुक्त निदेशक, डॉ. मनोज कुंडू संयुक्त निदेशक, प्रेम चंद संधू उप निदेशक, डॉ. पवन कुमार उप निदेशक और डॉ. महेंद्र सिंह विषय विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया।

भूजल पुनर्भरण द्वारा पानी की आपूर्ति में वृद्धि करके कृषि का विकास करने के लिए सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह और टीम के सदस्य सतबीर सिंह कादियान मुख्य अभियंता, सुरेश यादा एसई नारनौल, सतीश जेनेवा एसई झज्जर, अरुण मुंजाल एक्सईएन जेएलएन फीडर, आशुतोष यादव एक्सईएन (एम) नारनौल, संदीप मलिक एसडीओ फीडर व जयदीप जेई को सम्मानित किया गया।

फसलों की खरीद को सरल बनाने के लिए 'ई खरीद पोर्टल' की शुरुआत करने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक चंद्र शेखर खरे, हरियाणा वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक राजीव रतन और टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया।

कोविड-19 सर्वेक्षण के तहत डोर टू डोर सर्वे करने के लिए 'आशा सर्वेक्षण' ऐप विकसित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के परियोजना निदेशक डॉ. प्रभजोत सिंह और टीम के सदस्य डॉ. वी.के बंसल निदेशक, एमसीएच, डॉ. चंद सिंह मदन राज्य समन्वयक, कृष्ण लाल प्रशिक्षण और निगरानी समन्वयक, धरिंदर प्रोग्रामर आईटी, एनएचएम और अंकुश मित्तल, सॉफ्टवेयर डेवलपर तथा 'ई-संजीवनी ओपीडी' के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डॉ. अलका गर्ग उप निदेशक (मातृ स्वास्थ्य), डॉ. अभिषेक सलाहकार, एनएचएम, डॉ. दीपक जूनियर सलाहकार, एनएचएम को सम्मानित किया गय

'आयुष्मान भारत योजना' के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की महानिदेशक अमनीत पी कुमार और टीम के सदस्य डॉ. सविता मंधार कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), मोहित जूनियर प्रोग्रामर, मीनाक्षी डाटा एंट्री ऑपरेटर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। 'यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम' के डॉ. वीरेंद्र अहलावत डीडी (टीकाकरण), डॉ. शिवानी डब्ल्यूएचओ सलाहकार, डॉ. प्रेम सलाहकार, डॉ. रितु दहिया सलाहकार को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया गया।

'जनसहायक मोबाइल ऐप' विकासित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल, सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य सचिव कार्यालय और टीम के सदस्य राकेश कुमार अवर सचिव, जितेंद्र एसईओ, नवदीप गुप्ता एसए, विश्वास श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह, परीक्षक और हनी सचदेवा परीक्षक को सम्मानित किया गया।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत सभी सहकारी समितियों को जल्द से जल्द वेब पोर्टल rcsharyana.gov.in पर अपने रिकॉर्ड अपलोड करने का निर्देश दिया है।

गुरुग्राम के सैक्टर 52ए में चिह्नित की गई ज़मीन पर लगभग आठ एकड़ में फूलों की मंडी बनाई जाएगी। इस फूल मंडी को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप (पीपीपी) आधार पर विकसित करने की योजना है।

आयुष चिकित्सा पर्यटन की ओर बढ़ते कदम

मनोज प्रभाकर

भारत में सदियों से आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणालियों की स्वीकार्यता रही है। जीवनशैली से जुड़े कई गम्भीर रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में इन प्रणालियों की अहम भूमिका है। कुछ अर्से से वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा प्रणालियों में लोगों का रूझान बढ़ा है।

राजकीय प्रयासों के चलते हरियाणा में आयुष चिकित्सा पद्धति अपने मूल भरोसे की ओर लौट रही है। आयुष विभाग इन प्रयासों का निरंतर निर्वहन कर रहा है। इसके मुख्य धारा में आने से मरीजों को रोग के अनुसार चिकित्सा प्रणाली का चयन करने में आसानी होगी।

प्रदेश में इस समय 14 आयुर्वेद व एक होम्योपैथी कालेज हैं, इनमें से पांच कालेज निजी क्षेत्र में हैं। भिवानी, पंचकुला, पलवल, चरखीदादरी, कुरुक्षेत्र व नारनौल में आयुर्वेद अस्पताल हैं। इनके अलावा प्रदेश में 510 आयुर्वेद डिस्पेंसरी, 19 यूनानी डिस्पेंसरी व 23 होम्योपैथी डिस्पेंसरी हैं जिनमें हर रोज मरीज उपचार करा रहे हैं। 232 डिस्पेंसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रही हैं। पिछले वर्ष राज्य सरकार की ओर से दो स्पेशल थैरपी सेंटर तथा जिला सोनीपत में 3, चरखी दादरी में एक, अंबाला में दो, हिसार में 6 व यमुनानगर में दो आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।

गांवों में योगशालाएं

प्रदेश की 'व्यायाम एवं योगशालाओं' के सफल संचालन हेतु एक हजार आयुष सहायक तथा 22 आयुष कोचों की भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुबंध आधार पर की जा रही है। आयुष सहायकों को 11 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा, जोकि 18 से 35 वर्ष तक आयु वर्ग के होंगे। 22 आयुष कोचों की भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित तौर पर की जाएगी। चयन आयोग द्वारा भर्ती होने तक आयुष कोचों की भर्ती आउटसोर्सिंग 2 के तहत राज्य स्तरीय चयन कमेटी द्वारा की जाएगी। गांवों में योग शिक्षकों की भर्ती होने के बाद गांव के बच्चे, युवा, महिला व बुजुर्ग इन सुविधाओं का भरपूर फायदा ले सकेंगे।

हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 407 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर तथा 138 सब-केंद्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक मंजूरी पा चुका है। हरियाणा राज्य आयुष सोसायटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में निर्णय हुआ है कि इन वैलनेस सेंटरों तथा सब-केंद्रों को स्थापित करने पर लगभग 64.52 करोड़ रुपये खर्च किये होंगे। इनमें से 102 वैलनेस सेंटर जल्द बनेंगे। जो अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर, सोनीपत तथा पलवल में होंगे।

उल्लेखनीय है कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी को जिला स्वास्थ्य एवं आयुष सोसायटी के रूप में पुर्नगठित किया गया है जो स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की योजनाओं को चलाने के लिए कार्य करेगी।

पीएचसी में खुलेंगी आयुष विंग

राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एलोपैथिक) स्तर पर आयुष सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 419 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 419 आयुष चिकित्सक, 419 आयुष फार्मासिस्ट, 419 सेवादार और इतने ही अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन पदों के सृजन के साथ-साथ आबंटित की जा सकने वाली स्कीम के क्रियान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 36 करोड़ रुपए के बजट के आयुष विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के तहत 528 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 131 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। विभाग द्वारा इन 528 पीएचसी में से 109 पीएचसी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत आयुष स्टाफ नियुक्त किया जा चुका है।

पंचकर्मा सेंटर

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शहरों में पंचकर्मा सेंटर बनाने हेतु उचित कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को शीघ्र योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचकर्मा सेंटर की बहुत मांग है। लोगों को लम्बे समय तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए सभी बड़े शहरों में इन केन्द्रों को प्राथमिकता आधार पर स्थापित करना होगा। हाल में 16 सेंटर चल रहे हैं।

मेवात में यूनानी मेडिकल कालेज

मेवात के अकेड़ा गांव में राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोला जाएगा। क्षेत्र के लोगों की मांग पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में यह पहला यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल होगा। इसका निर्माण 6 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जो अकेड़ा गांव की पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस पर करीब 10.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महाविद्यालय में यूनानी मेडिसन एवं सर्जरी में स्नातक (बीयूएमएस) चिकित्सकों की सीटें होंगी।

श्री अनिल विज कहते हैं कि सरकार की मंशा प्रदेश के सभी जिलों में आयुष विंग स्थापित करने की है। परन्तु यूनानी चिकित्सकों की कमी के कारण इसमें दिक्कत आ रही है। प्रदेश में इस समय 19 यूनानी चिकित्सक विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परन्तु इस कॉलेज के खोले जाने से यूनानी चिकित्सा को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

आयुष विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स

श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में 5 विषयों की 24 सीटों हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यों में शुरू हुए हैं। इससे प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सों को उनके गृह

कोरोना वक्त में आयुष के प्रति लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार की ओर से आयुर्वेद व अन्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हरियाणा में आयुष पर्यटन की प्रबल संभावनाएं हैं।

श्री अतुल कुमार, निदेशक आयुष विभाग

प्रदेश में ही स्नातकोत्तर करने का अवसर मिलेगा, जिससे राज्य में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी। इससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा और श्रीकृष्णा आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल में उचित आधारभूत संरचना, शैक्षणिक तथा चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ेंगी।

आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बलदेव कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में शरीर रचना, क्रिया शरीर, शल्य चिकित्सा की 6-6 सीटें तथा बाल रोग एवं पंचकर्मा की 3-3 सीटें स्वीकृत की गई है।

माना जा रहा है कि यह शैक्षणिक संस्थान प्राचीन और आधुनिकता का समावेश होगा, जिसमें आयुष के सभी संकायों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ताकि हरियाणा के युवाओं को अपनी प्राचीन एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान हो सके।

नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेद

माता मनसा देवी कॉम्पलेक्स में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ आयुर्वेद का निर्माण होने जा रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाईक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लिंक से इस संस्थान का शिलान्यास किया।

पंचकूला में आयुर्वेद संस्थान के बनने से ट्राईसिटी के साथ-साथ हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के लगभग दो करोड़ लोगों को चिकित्सा सेवा का सीधा लाभ मिलेगा तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगें।

इस परियोजना पर लगभग 270.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 250 बेड के आईपीडी अस्पताल के साथ आयुर्वेद उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में हर साल 500 से अधिक छात्रों को यूजी, पीजी और पीएचडी की सुविधाएं मिलेंगी।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा प्रणाली की वैज्ञानिक विश्वसनीयता देने के लिए एक कारगर राष्ट्र स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के सभी स्तरों में आयुष की मुख्यधारा में परिकल्पना की गई है।

जैविक विविधता का केंद्र मोरनी हिल्स

मोरनी व कलेसर में प्राकृतिक वन बहुतायत है। मोरनी क्षेत्र को औषधीय पौधों की जैविक विविधता का एक हॉट स्पाट केन्द्र माना गया है। विश्व औषधीय वन परियोजना के मुताबिक पतंजलि योगपीठ के 30 वैज्ञानिकों ने निरंतर मोरनी क्षेत्र में तीन बार सर्वे किया है और 983 जड़ी-बूटियों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें से 300 नई प्रजातियां है और 53 प्रजातियों की पहली बार पहचान की गई है। मोरनी के 715 हैक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगपीठ द्वारा क्षेत्र में कुल 125 औषधीय वाटिकाएं विकसित की गई है।

हरियाणा में अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग माइनिंग वाहनों पर नकेल कसने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को अंतरराज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर ऐसे वाहनों पर सख़्त निगरानी के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की भी सुविधा प्रदान की है और इसे एक्टिव मोड में लाया गया है।

जैविक खेती से बंजर ज़मीन को बनाया उपजाऊ

दिन-प्रतिदिन खेती के लिए अधिक रसायनों के प्रयोग से ज़मीन बंजर होती जा रही है। लोगों को रसायनयुक्त उत्पाद मिल रहे है, जिसके चलते कम उम्र में ही लोग रोगग्रस्त हो रहे है। भूमि को उपजाऊ बनाने और लोगों को शुद्ध व जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल रेवाड़ी के धारूहेड़ा गांव के किसान संजय ने की है। टैक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री में 28 साल तक देश व विदेश में काम करने के बाद उन्होंने खेती की ओर रूख़ कर लिया है। गत तीन साल से उन्होंने जैविक खेती करनी शुरू कर दी। आरंभ में डेढ़ से दो साल तक ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए अथक प्रयास किए और देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और अन्य देसी तरीकों का इस्तेमाल किया।

ज़मीन को बनाया उपजाऊ

संजय ने बताया कि उनके परिवार की मिलाकर 35 एकड़ ज़मीन है और जो लीज में दी हुई थी। धीरे-धीरे ज़मीन बंजर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ज़मीन को पुनर्जीवित करने की ठानी। उन्होंने बताया कि जब वह विदेश से लौटे तो उन्होंने देखा कि लोगों को रसायनयुक्त उत्पाद अधिक मिल रहे हैं, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने के मकसद से जैविक खेती करना शुरू किया। आरंभ में उन्हें टमाटर की खेती में काफ़ी नुक़सान भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने रसायनों का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। देसी खाद व देसी तरीकों का इस्तेमाल किया।

बी-कीपिंग से दोहरा मुनाफ़ा

संजय अपनी ज़मीन में 15 सब्ज़ियां जैसे आलू, प्याज, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी, मटर, पालक, मैथी, शिमला मिर्च व अन्य मौसमी सब्ज़ियों की खेती कर रहे हैं, जिनकी बिक्री आसानी से हो जाती है। वह मौसमी सीजन में तरबूज़, घीया, तोरी, करेला व कद्दू की सब्ज़ियों की खेती भी करेंगे। उन्होंने बताया कि गत वर्ष उन्होंने सरसों की फसल में 20 बी-बॉक्स रखे और

इन बॉक्सों से एक क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ। यह शहद उन्होंने ट्रायल के रूप में बनाया था और शहद उनके परिवार के दोस्तों, रिश्तेदारों व जानकारों ने खरीदा। शुद्ध जैविक शहद 650 रुपए किलो और 350 रुपए आधा किलो के हिसाब से बिका। लोगों ने इतना अधिक पसंद किया कि इस साल भी उनसे शहद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खेती के साथ बी-कीपिंग करके भी किसान मुनाफ़ा कमा सकते हैं। उनकी योजना मछली पालन, मुर्गीपालन व पशुपालन करने की भी है।

जैविक उत्पाद की मांग बढ़ी

संजय ने बताया कि वह अन्य किसानों को भी जैविक खेती के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में इस खेती के प्रति इतनी अधिक जागरूकता नहीं है और किसानों को लगता है कि जैविक खेती से नुक़सान होगा। उनका लक्ष्य 10 से 15 किसानों को एकत्रित करके किसान उत्पादक संगठन का गठन करना है। वह जैविक सरसों, बाजरा व गेहूं की खेती भी करते हैं और सरसों का तेल भी तैयार करते हैं। गत वर्ष 180 रुपए प्रति लिटर की दर से सरसों का तेल बिका। इसके अतिरिक्त जैविक बाजरा की फ़सल को लोगों ने इतना पसंद किया कि खेतों से ही बाजरा खरीदकर ले गए। बाजरा को मंडी में ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका कहना है कि जैविक उत्पादों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वह ख़ुशी जाहिर करते हैं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के काम को छोड़कर वह वापिस खेती की ओर आ गए हैं। लोगों को गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। वह जैविक खेती से लगभग 25 लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहे हैं, इसमें कई लेबर दिहाड़ीदार भी है।

संगीता शर्मा

सेब मार्केट के दूसरे चरण के मास्टर प्लान को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने पंचकूला जिला के पिंजौर में स्थापित की जा रही सेब, फल व सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट के दूसरे चरण के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। यह मार्केट 175 करोड़ रुपए की लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। यह कार्य 96.53 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

पहले चरण का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और एप्पल शेड, शेड से सटे कार्यालय, एंट्री गेट, बाउंड्री वॉल सहित टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का काम दिसंबर 2020 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना के पहले चरण पर लगभग 28.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

यह भी तय किया गया कि शुरू में 50 दुकानों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें मार्केट परिसर में आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा दुकानों के लिए 50 प्लाट भी बेचे जाएंगे।

मार्केट में कोल्ड/कंट्रोल्ड एटमॉसफियर स्टोर्स, फ्रूट राइपनिंग सेंटर, पेट्रोल पंप/सीएनजी स्टेशन, होटल, ढाबा, पैक हाउस, पैकेजिंग यूनिट्स, ट्रेड सेंटर और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए साइटों का पट्टों के आधार पर लंबी अवधि के लिए आवंटन किया जाएगा।

मार्केट में एप्पल शेड, आलू-प्याज शेड, टमाटर-अन्य फल और सब्जी शेड, किसान और रिटेल शेड, रैफ्रिजरेटिड फल और सब्जी हॉल, प्रशासनिक भवन, किसान रैस्ट हाऊस, पार्किंग स्थल और सड़कों की सुविधा होगी।

रेडियो से ले सकते हैं कृषि संबंधी जानकारी

चौधरी चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय,हिसार सात सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने विश्वविद्यालय के जींद, पानीपत व कुरुक्षेत्र कृषि विज्ञान केंद्रों में एक साथ तीन सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पहले हिसार, झज्जर व रोहतक में पहले से ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। सिरसा के कृषि विज्ञान केंद्र के सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी जल्द ही विधिवत रूप से शुभारंभ किया जाएगा।

प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि रेडियो स्टेशनों के स्थापित होने के बाद किसानों व वैज्ञानिकों के संबंध अधिक घनिष्ठ होंगे और किसानों को हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि इनसे किसानों को फसलों की उन्नत किस्मों के साथ-साथ उनकी बिजाई संबंधी जानकारी, बिमारियों व कीटों और समाधान संबंधी जानकारी, मौसम सम्बन्धी जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन एवं गृह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रेडियो स्टेशन स्थानीय संस्कृति, कला एवं ज्ञान को भी बढ़ावा देंगे।

कार्यक्रमों की रूपरेखा

विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ आर.एस. हुड्डा ने कहा कि यह सभी रेडियो स्टेशन हरियाणा सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व आत्मा स्कीम के तहत स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में सबसे पहले 29 नवंबर 2009 को सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई और एफ.एम. 91.2 मैगाहर्टज पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। इन रेडियो स्टेशन से दिन में दो बार सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तथा शाम को 2:30 बजे से 4:30 बजे कृषि पशुपालन, सरकारी योजनाओं, मौसम संबंधी जानकारी व स्थानीय कलाकारों द्वारा हरियाणवी संस्कृति कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

डेयरी संचालन से लाखों की कमाई

मंडी आदमपुर की सुनीता बिश्नोई अपने भाई के साथ मिलकर डेयरी संचालन कर अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। दोनों ने स्नातक की पढ़ाई की है।

सुनीता ने बताया भाई सुनील व मां के सहयोग से वर्ष 2014 में 7 पशुओं से डेयरी की शुरुआत की थी। आज उनके पास 50 भैंस व 15 गाय हरियाणा नस्ल की हैं। दूध के कारोबार में उनको साल में खर्च निकाल कर 12 से 15 लाख रूपए की बचत हो जाती है। उन्होंने लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार से प्रशिक्षण लिया था। उन्हें प्रगतिशील पशुपालक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

आज उनके यहां रोजाना करीब 250 लीटर दूध उत्पादन होता है जिसे वह 60 से 80 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से बाजार में बेचती हैं। बाजार में 10 किलो पनीर की बिक्री भी हो जाती है। भैंस का शुद्ध देसी घी 800 रूपए व गाय का शुद्ध घी 1200 रूपए प्रति किलो बिक जाता है। उनके पास मात्र ढाई एकड़ जमीन है जिसमें वे डेयरी का संचालन करते हैं।

हरियाणा सरकार ने पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का भाव (राज्य परामर्श मूल्य) 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है, जोकि देश में सर्वाधिक है।

हरियाणा राज्य तालाब विकास प्राधिकरण द्वारा गंदे पानी वाले तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना के तहत 200 तालाबों पर काम शुरू किया गया।

हैफेड के बिक्री केंद्रों पर मिलेंगे किसानों के उत्पाद

हरियाणा सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के उत्पादों को अब हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल की उपस्थिति में हैफेड कॉरपोरेट कार्यालय, पंचकूला में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड (हैफेड) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है। हैफेड की इस पहल से न केवल किसान उत्पादक संगठनों को मदद मिलेगी, बल्कि हैफेड के आउटलेट के माध्यम से उचित दर पर गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने में उपभोक्ता भी सक्षम होंगे।

> राज्य सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से 1000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब तक 486 एफपीओ में लगभग 75 हजार किसानों को जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ के लिए ट्रेड सेंटर की परिकल्पना की जा रही है और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रयोगशाला भी प्रस्तावित है।
>
> अर्जुन सैनी, महानिदेशक, बागवानी विभाग, हरियाणा

ये होंगे उत्पाद

हैफेड ने शहद, आंवला मुरब्बा, बेलगिरी मुरब्बा, सेब मुरब्बा, हरड़ मुरब्बा, अदरक मुरब्बा, लहसुन मुरब्बा आदि को अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने हेतु किसान उत्पादक संगठनो (एफपीओ) को विपणन सहायता देने का निर्णय लिया है। शहद आधारित उत्पाद (शहद के साथ गुलकंद व दालचीनी, शहद व इलायची के साथ गुलकंद), विभिन्न प्रकार के सिरका (हनी सिरका, एप्पल साइडर, जामुन हनी) और हल्दी इत्यादि हैफेड के बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे।

उच्च गुणवत्ता के उत्पाद किफायती दरों पर

हैफेड के साथ शुरुआत करने के लिए दो एफपीओ नामतः अतुल्य बीमास्टर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जींद और फतेहाबाद एकता हनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जंडली कलां (फतेहाबाद) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। एफपीओ द्वारा निर्मित लगभग 27 उत्पादों को हैफेड के बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। भविष्य में अन्य उत्पादों (एफपीओ द्वारा निर्मित) को बिक्री हेतु दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, भविष्य में इसी प्रकार नए एफपीओ को भी जोड़ा जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकें।

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों को हैफेड का मंच प्रदान किया जा रहा है क्योंकि हैफेड की बाजार में काफी प्रसिद्धि है। किसानों के उत्थान के अंतर्गत एफपीओ को ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किफायती दरों को ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
>
> हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल

सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड (हैफेड) हरियाणा में सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्र के संगठनों में से एक है, जो किसानों और उपभोक्ताओं के हित में समान रूप से सेवा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रस्तावित ''हैफेड बाजार'' आउटलेट जनवरी, 2021 के अंत तक हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों में खोले जाएंगे। संवाद ब्यूरो

सुरेंद्र सिंह विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ पैनल में चयनित

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह धनखड़ का स्विट्जरलैंड (जेनेवा) स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नव सुधार आयोग आधारित कृषि की स्थायी समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में चयन हुआ है। इस आयोग में चयन के लिए उनका नाम भारत सरकार के भू विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस आयोग में चयनित होने वाले डॉ. सुरेंद्र सिंह धनखड़ देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों से एकमात्र कृषि मौसम विज्ञानी हैं। यह चयन उनके द्वारा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर किया गया है। यह आयोग मौसम, जलवायु, जल और संबंधित पर्यावरण सेवा अनुप्रयोगों के लिए कार्य करता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर इससे संबंधित विसंगतियों के प्रति जागरूक करना है।

एशिया महाद्वीप का करेंगे प्रतिनिधित्व

कृषि मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह धनखड़ कृषि मौसम विज्ञान से सम्बंधित सूखा निगरानी प्रणाली, दृष्टिकोण, प्रभावों, संभव कृषि घाटा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियों के मूल्यांकन के लिए अपना योगदान देंगे। वे विश्व स्तर पर एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के इस तकनीकी आयोग का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ता, समुदायों और समाज द्वारा सामाजिक,आर्थिक लाभों की सूचना देने और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मौसम, जलवायु, जल, महासागर और पर्यावरण से संबंधित सेवाओं और अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिए योगदान करना है।

देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में से इस प्रतिष्ठित आयोग के लिए चयनित होने वाले डॉ. सुरेंद्र कुमार धनखड़ एकमात्र वैज्ञानिक है। वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं।

किसानों को खेती के लिए विशेष अनुदान

प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों के कल्याणार्थ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 193.63 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

ये हैं योजनाएं

- सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' के अंतर्गत किसानों को गेहूं, दलहन की फसलें व मोटे अनाज,गन्ना तथा कपास की फसलों में खरपतवार नाशक, जिप्सम कीटनाशकों, जैव उर्वरक, बीज वितरण तथा स्प्रे पम्पों आदि पर अनुदान दिया जाता है।
- 'आत्मा' स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रेनिंग के अलावा भ्रमण, प्रदर्शन इत्यादि गतिविधियां करवाई जाती हैं।
- 'इन-सीटू क्रोप रेजीड्यू मैनेजमैंट स्कीम', 'सब-मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम' तथा 'अनुसूचित जाति के समूहों' हेतु कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
- अन्य किसानों की भांति अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि भूमि के लिए भी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' बनाए जाते हैं ताकि वे मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार अपनी फसलों की बिजाई करके बेहतर उपज ले सकें।
- प्रदेश में राज्य स्तरीय स्कीम के तहत बैटरी चालित 200 स्प्रे पम्पों पर सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।
- इन किसानों को बॉयोगैस स्कीम के तहत एक क्यूबिक के बॉयोगैस प्लांट पर 10 हजार रुपए तथा 2 से 6 क्यूबिक तक के बॉयोगैस प्लांट पर 13 हजार रुपए प्रति संयंत्र अनुदान दिया जाता है।
- भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, फव्वारा संयंत्र प्रणाली तथा टपका सिंचाई योजनाओं के तहत किसी भी सिंचाई प्रणाली पर कुल खर्च का 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- सरकार द्वारा एल्युनियम आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर अनुसूचित जाति के किसानों को कुल खर्च का अधिकतम 28,650 रुपए का लाभ दिया जाता है।
- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के तहत जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है।
- हल्दी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करके अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

संवाद ब्यूरो

बहुत फायदेमंद है बथुए की सब्जी

हरी साग-सब्जियां किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं हैं। सर्दियों में पालक के अलावा बथुए का सेवन काफी लाभदायक होता है। बथुए में विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा आंवले से ज्यादा होती है। इसमें आयरन, फॉस्फोरस और विटामिन ए और डी काफी मात्रा में पाए जाते हैं।

- बथुए की पत्तियों को कच्चा चबाने से सांस की बदबू, पायरिया और दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं में फायदा होता है।
- कब्ज से राहत दिलाने में बथुआ बेहद कारगर है। लकवा, गैस की समस्या में यह काफी फायदेमंद है।
- भूख में कमी आना, खाना देर से पचना, खट्टी डकार आना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी बथुआ खाना फायदेमंद है।
- बथुआ और गिलोय का रस लेकर एक सीमित मात्रा में दोनों को मिलाएं, फिर इस मिश्रण का 25-30 ग्राम रोज दिन में दो बार लें।

- बथुए को 4-5 नीम की पत्तियों के रस के साथ खाया जाए तो खून साफ हो जाता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है।
- बच्चों को कुछ दिनों तक लगातार बथुआ खिलाया जाए तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। बथुआ पेट दर्द में भी फायदेमंद है।
- बथुए को उबालकर इसका रस पीने और सब्जी बनाकर खाने से चर्म रोग जैसे सफेद दाग, फोड़े-फुंसी, खुजली में भी आराम मिलता है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने दाना मटर की नई रोग प्रतिरोधी किस्म एच.एफ. पी.-1428 विकसित की। किस्म को अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग द्वारा विकसित किया गया।

तीन लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त फसली ऋण की सुविधा सहकारी एवं राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। पहले यह सुविधा केवल 1.50 लाख रुपए तक उपलब्ध थी।

फसलों का हुआ बीमा, किसान हुए चिंतामुक्त

संगीता शर्मा

प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों के कारण फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को ख़ासा नुक़सान झेलना पड़ता है। इस हानि से उबारने के लिए बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की शुरुआत खरीफ 2016 में हुई। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौं तथा सूरजमुखी फसल को सम्मिलित किया जा रहा है।

योजन का उद्देश्य

खेती में किसानों की निरतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना, जो किसानों को उत्पादन जोखिमों से बचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा, फसल विविधिकरण तथा कृषि क्षेत्र के विकास व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में योगदान देना है।

इस योजना को राज्य में कलस्टर दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों को तीन कलस्टर में बांटा गया है। कलस्टर में सम्मिलित जिले एवं बीमा कंपनी निम्न प्रकार से है:-

कलस्टर	जिले	बीमा कंपनी (वर्ष 2019-20)के लिए
1.	सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला, रेवाड़ी	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला जींद, महेंद्रगढ़	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3.	यमुनानगर, पानीपत, पलवल, रोहतक, फतेहाबाद, झज्जर, मेवात, चरखीदादरी	बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बीमा कंपनियों का चयन

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए भारत सरकार द्वारा 19 बीमा कंपनियों को अधिकृत किया है। इन्ही अधिकृत कंपनियों में से ई-टेंडर द्वारा न्यूनतम औसत प्रीमियम देने वाली कंपनी को कलस्टर के आधार पर चयन किया जाता है। प्रीमियम एवं अनुदान इस योजना के अधीन किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ में बीमित राशि का दो प्रतिशत, रबी में बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत है। बाकी का हिस्सा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात में वहन किया जाता है।

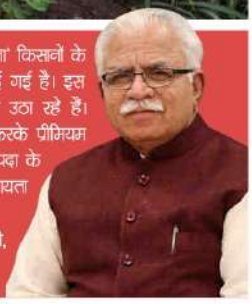

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इस योजना का किसान अधिक लाभ उठा रहे हैं। किसानों की फसलों का बीमा करके प्रीमियम लिया जाता है और प्राकृतिक आपदा के समय मे उसका क्लेम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

जोखिम : इस योजना के तहत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिम, द्वेषपूर्ण नुक़सान तथा अन्य रोके जा सकने योग्य जोखिमों के इलावा सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हानियां शामिल की जाती है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में जोखिम को तीन भागों में बांटा गया है, जोकि निम्नानुसार है:-

क) खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक)

यह जोखिम किसान की उत्पादकता को निश्चित करता है। इस जोखिम में सरकार सीजन से पहले फसल तथा जिलावार एक निश्चित उत्पादक सीमा तय करती है। जिसे पिछले सात में से बेहतर पांच साल के आंकड़ों से तय किया जाता है। बीमित फसल की कटाई के समय विभाग के कृषि विकास अधिकारी प्रत्येक गांव में प्रत्येक बीमित फसल पर चार फसल कटाई प्रयोग करते हैं। जिनकी तुलना सरकार द्वारा घोषित उत्पादक सीमा से की जाती है। कम रहने पर किसान को उसके अनुपात का क्लेम दे दिया जाता है।

क्लेम का आकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाता है:-

क्लेम (रुपए प्रति हैक्टेयर)= प्रारंभिक पैदावार-वास्तविक पैदावार X बीमित राशि / प्रारंभिक पैदावार

इस जोखिम में किसान को क्लेम प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। बीमित क्षेत्र (इकाई) में सभी बीमित किसानों को उपरोक्त सूत्र के आधार पर उनके बीमित क्षेत्रफल के अनुसार क्लेम दिया जाता है।

ख) फसल कटाई के बाद हुई हानि

यदि किसान की फसल कटाई के अधिकतम दो सप्ताह तक खेतों में सुखाने के लिए रखने की स्थिति में चक्रवात, चक्रवातीय बारिश तथा बेमौसमी बारिश के कारण फसल को नुक़सान होता है तो वह योजना के फसल कटाई के बाद हुई हानि की श्रेणी में आती है। नुक़सान का आंकलन खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा संबंधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए किसान को 72 घंटे के अंदर नुक़सान की सूचना संबंधित जिले के कृषि विभाग में देनी होती है।

ग) स्थानीय आपदाएं :

यदि किसान की फसल ओलावृष्टि तथा जल भराव तथा आसमानी बिजली के कारण नष्ट हो जाती है तो वह स्थानीय आपदा की श्रेणी में आती है। नुक़सान का आंकलन खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा संबंधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह सर्वेक्षण 12 दिन के अंदर किया जाना अनिवार्य होता है। इसका लाभ लेने के लिए किसान को 72 घंटे के अंदर नुक़सान की सूचना संबंधित जिले के कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में देनी होती है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कई प्रकार की समितियां बनाई गई है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

बीमित राशि तथा खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की प्रीमियम राशि।

फसल का नाम	बीमित राशि	किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति एकड़
धान	33,999.69	679.99
बाजरा	15,999.66	319.99
मक्का	17,000.04	340.00
कपास	33,000.11	1650.00
गेहूं	26,000.26	390.00
जौ	17,000.04	255.00
सरसों	17,500.24	262.50
चना	13,000.13	195.00
सूरजमुखी	17,000.04	255.00

केंद्र सरकार द्वारा योजना में प्रस्तावित मुख्य बदलाव

केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्ष के अनुभव के आधार पर योजना में कुछ बदलाव किए गए है। जैसे बीमा कंपनी का चयन कम से कम तीन वर्ष के लिए किया गया, योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई तथा राज्य को जोखिम तय करने का अधिकार दिया गया।

क्या कहना है कि प्रगतिशील किसानों का

पलवल के किठवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसान बिजेंद्र का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए हितकारी है और किसानों को इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए। उनका कहना है कि लोगों में अभी इस योजना के प्रति जागरूकता की कमी है, जबकि उन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाया हैं। बढा गांव के प्रगतिशील किसान ओमबीर सिंह भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। उनका कहना है कि मौसम की मार, बारिश व आंधी तूफ़ान के कारण जब किसान की फसल ख़राब होती है तो उसे बहुत हानि होती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राहत प्रदान करती है और वित्तीय सहायता से आर्थिक मदद मिलती है। एक अन्य किसान हरचंदी का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जागरूक किसान फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बीमा योजना का दायरा बढ़ाना चाहिए और सब्ज़ियों व दलहन वाली फ़सलों का भी बीमा होना चाहिए। इससे किसानों को दोगुना लाभ होगा।

मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत आवंटित राशि को संबंधित योजनाओं में जल्द लगाने का प्रयास करें जिससे जनता को इसका फायदा हो। वे विकास कार्यों के पूरा होने पर प्रमाण-पत्र भी निदेशालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें। डिप्टी सीएम ने जिन-जिन जिलों में मनरेगा का कार्य गति नहीं पकड़ पाया है उनमें संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलबी की और प्रदेश के हर गांव में मनरेगा स्कीम के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कहा।

श्री चौटाला ने बताया कि मनरेगा के तहत दिए गए टारगेट को विभाग ने इस बार समय से पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए 140 लाख कार्य-दिवस निर्धारित किए गए थे जिनमें से 125 लाख कार्य-दिवस नवंबर 2020 तक ही पूरे कर लिए हैं जो कि कुल कार्य का 90 प्रतिशत है। पिछले वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाने वाले काम के लिए 91.19 लाख कार्य-दिवस तय किए गए थे।

अधिकारियों को गरीबों के पशुओं के लिए मनरेगा के तहत बनाए जाने वाले कैटल-शैड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए इन कैटल-शैड को बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। 15 जनवरी 2021 तक 10 हजार शैड के निर्माण करवाने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को 'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत आश्रय-रहित विमुक्त घुमंतू जाति के पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने के लिए ऐसे घरों की निर्माण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।

आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 3,870 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं जिसके तहत उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया।

लोकसाहित्य की समृद्ध भाषा 'हरियाणवी'

भारतीय संविधान की सूची में भारत के अलग-अलग राज्यों की 22 भाषाएं शामिल हैं, किन्तु हरियाणवी भाषा को अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। इसके पीछे कारण जो भी हों, लेकिन हरियाणवी भाषा के हजारों साल की यात्रा को नकारा नहीं जा सकता।

हरियाणवी बोली का सीधा सम्बन्ध वैदिककाल से है, वैदिककाल में प्रचलित संस्कृत भाषा के असंख्य शब्द हरियाणवी बोली में आज भी ज्यों के त्यों हैं। वैदिककाल में जहां संस्कृत साहित्य की भाषा थी, वहीं आज हरियाणवी लोकभाषा के रूप में जनमानस की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का काम कर रही है। इसका प्रमाण हरियाणवी बोली यानी भाषा में अनेक वैदिककालीन शब्दों का होना है। इतना ही नहीं, संस्कृत के असंख्य शब्द हरियाणवी भाषा में समाहित हैं। इससे पता चलता है, कि कालान्तर में यह भाषा संस्कृत के साथ-साथ लोकजीवन की भाषा रही है। संस्कृत के पश्चात् प्राकृत-पाली भाषा का स्वरूप तक चलता रहा, इन भाषाओं में हजारों शब्द हरियाणवी भाषा के देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है, इसमें भी हरियाणवी भाषा के अनेक अंश दिखाई देते हैं। गोरखनाथ की वाणी का यह उदाहरण - कंटक देश, कठोर नर, भैंस मूतर को नीर, करमों का मार्‌या फिरै, बांगर बीच फकीर।

आदिकाल में चन्द्रबरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हरियाणवी अंश देखने को मिलते हैं। जैसे- भगा हुआ जो मारिया बहिणु म्हारा कन्त।

कबीर जैसे संत ने भी अपनी वाणी में हरियाणवी भाषा के उदाहरण दिए हैं, जो इसकी प्राचीनता के द्योतक है। यह परम्परा आगे बढ़ी और संत आत्मानंद ने अपनी- 'राम तेरा रम्या हुआ जर जर में' में भी हरियाणवी भाषा की परम्परा को आगे बढ़ाया, इसके पश्चात् सूरदास, जो स्वयं हरियाणवी थे, ने भी अपनी रचनाओं में हरियाणवी लोकभाषा को प्रमुख स्थान प्रदान किया । इसके पश्चात् अनेक सूफी संतों तथा रामकाव्य से जुड़े हुए भक्तों ने हरियाणवी बोली को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इस भाषा को और अधिक उत्साह एवं बल उस समय अधिक मिला, जब दिल्ली में अमीर खुसरो ने 13वीं सदी में हरियाणवी बोली में जकड़िया, कड़कों, नुस्खों, सूखनों आदि की रचना कर इसकी प्रामाणिकता का सबूत अपने साहित्य लेखन के माध्यम से दिया। खुसरो का सशक्त उदाहरण- 'खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाय, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाय।'

जिसे लोगों ने खड़ी बोली कहा उसका विकास भी हरियाणवी से ही हुआ है। उसके पश्चात संतोष सिंह, हाली, बाबा फरीद आदि कवियों ने हरियाणवी भाषा एवं शब्दों का सदुपयोग करते हुए अपनी रचनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, दक्खिनी हिन्दी में हरियाणवी भाषा के अनेकों ऐसे शब्द पाए जाते हैं, जिससे इसकी प्रामाणिकता को और अधिक बल मिलता है। कहना न होगा, रामायण, महाभारत, गीता सरीखे ग्रंथ में भी हरियाणवी भाषा विद्यमान है।

परम्परा आगे बढ़ती चली और अंग्रेजों तक जा पहुंची। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया में बांगरू, हरियाणवी तथा जाटू के नाम से इस भाषा को कलमबद्ध किया। रोहतक के तत्कालीन डी.सी. श्री ई. जॉसफ ने हरियाणवी भाषा की जाटू ग्लासरी बनाई। हरियाणवी पर बांगरू का संरचनात्मक अध्ययन के नाम से डॉ. जगदेव सिंह ने डिस्क्रीप्टिव ग्रॉमर ऑफ बांगरू के माध्यम से हरियाणवी लिपि का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर इसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता को स्पष्ट किया। डॉ. नानक चन्द ने हरियाणवी भाषा का उद्गम और विकास ग्रंथ के माध्यम से भी इस भाषा की प्रमाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही शंकरलाल यादव, रघुवीर मथाना व डॉ. बाबू राम ने हरियाणा लोकसाहित्य के इतिहास के माध्यम से हरियाणवी का जो इतिहास लिखा है, वह इसकी समृद्ध एवं साहित्यिक उर्वरा परम्परा को दर्शाता है।

वैदिक संस्कृत एवं हरियाणवी भाषा - हरियाणवी भाषा का मूल वैदिक काल में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आरणी, आअ्‌ल, आस, खर, खारी, गौ, जणी (स्त्रियों का समूह), जार, बाण, नाड़ी, वाह, कार, करसी, फाअ्‌ल, सिरी आदि शब्द वैदिक कालीन है। इसके साथ ही तत्सम् शब्दों में भी- तकु का ताकू, झष का झक्ख, जनी का जणी, जत्रु का जात्थर, गोष्ठ का गितवाड़ा, गर्तारूह का गढ़वाला, गुर का गरल, नुकूल का न्यौल, ननान्द्र का नणदी, परुस का पुरस, पटुर का पट्ट, पीलू का पील्ह, सिंह का मीं, यौवन का जोब्बन, लवण का लामणी, वकल का बक्कल, महिष का महैस, पिक्के का छीका, स्थूणा का थूण आदि असंख्य जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता ऐसे शब्द हैं, जो हरियाणवी को वैदिक कालीन होने की पुष्टि करते हैं।

संस्कृत और हरियाणवी भाषा - लौकिक संस्कृत के साथ हरियाणवी की तुलना करें, तो ज्ञात होता है कि सैकड़ों शब्द ऐसे हैं, जो हरियाणवी में संस्कृत के तुल्य ही हैं और सहस्त्रों शब्द तद्भव या सादृश्य दिखाई पड़ते हैं। विद्वानों के अनुसार संस्कृत का चरम गौरव काल मोटे रूप में 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. रहा है। यदि वर्तमान हरियाणवी शब्दावली की संस्कृत-शब्दावली से तुलना करें, तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि हरियाणवी संस्कृत के समानान्तर अपनी सत्ता बनाए हुए थी। आज जैसे उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों की हिन्दी भाषा-भाषी कहा जाता है, लेकिन उनमें ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी भी सशक्त हैं, इसी प्रकार संस्कृत के साथ-साथ हरियाणवी भाषा की स्थिति रही होगी। यदि संस्कृत साहित्य की भाषा थी, तो हरियाणवी लोकभाषा रही होगी। इसकी पुष्टि के लिए जैसे - अंबर का अंबर, करद का करद, कुरंड का कुरंड, कोट का कोट, गाध का गाध, चारण का चारण, चित का चित, चिता का चिता, चीर का चीर, छेद का छेद, जग का जग, दया का दया, मण का मण, रंक का रंक, रस का रस, राज का राज, रीढ का रीढ, रूप का रूप, सार का सार आदि।

प्राकृत-पालि और हरियाणवी भाषा - प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के प्रगति-' म पर विचार करते हुए विद्वानों की राय है कि प्राकृत भाषाओं का प्रथम स्तर 2000 ई. पू. से ही आरंभ हो गया था। वैदिक भाषा के साथ-साथ जन-जीवन की जो स्वाभाविक (प्राकृत) काव्य भाषा थी, किन्तु वह भी प्रादेशिक भिन्नता लिए हुए थी। प्राकृत का यह रूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति तक चलता रहा। इनका काल मुख्य रूप से 900 ई. पू तक माना जाता है। हरियाणवी भाषा में प्राकृत एवं पाली के अनेक शब्द मिलते हैं जैसे- जैसे -कड्ढई -काढ्ढै से (निकलता है), कढई-काढै से (उबालता है), खिज्जई-खिज्जै से (खिन्न होता है), जुज्झइई-जूज्झै सै (जूझता है), जोअइ-जोवै सै (जलाता है), झखई-झींक्खै से (झींसणा है।), तावई-तावै से (गर्म करता है) हरियाणवी की तुलना प्राकृत की विभिन्न शैलियों से करने पर यह शौरसेनी-प्राकृत के अधिक निकट ठहरती है। **क्रमशः**

डॉ. महासिंह पूनिया, कुरुक्षेत्र

वर्ष नूतन को हमारा सहर्ष नमस्कार !!

नव वर्ष की सुबह ने नील गगन पर
स्वर्ण-रश्मियों का किया शृंगार,
नवल ख़ुशबूओं के पारिजात महके
साल बीस इक्कीस का हुआ सत्कार!
जगह-जगह झर रहे हर्ष के तुषार!
वर्ष नूतन को हमारा सहर्ष नमस्कार!!

अभिनंदन कर लो नव बेला का
देखो कुदरत में आया नया निखार,
हुई सुगंधित-सुरभित सिंदूरी सुबह
खिलखिलाया डाली पर हार-सिंगार!
खुशियां हों जीवन में सबके लाखों-हज़ार!
वर्ष नूतन को हमारा सहर्ष नमस्कार!!

हर कली-कोंपल के मुखड़े पर
टपक रही खुशियों की बौछार,
हर फूलों के बागों में महकी
नए साल की नवेली बसंत-विहार!
बजती रहे हर पल खुशियों की झंकार!
वर्ष नूतन को हमारा सहर्ष नमस्कार!!

सदा प्रदीप्त रहे प्रभाकर वतन का
हमेशा यश-कीर्ति का फैले उजियार,
विश्व में चमकें बुलंदियों के सितारे
मेरे देश का अभिनंदन करे संसार!
गा रहे सप्रेम भारतीय मंगलाचार!
वर्ष नूतन को हमारा सहर्ष नमस्कार!!

सुरेंद्र कुमार 'सूरज'

श्री स्थाणेश्वर महादेव मंदिर

पांडवों ने पूजा कर लिया था विजयी होने का वरदान

इस मंदिर का जिक्र महाभारत एवं पुराणों में वर्णित है। यह पावन तीर्थ थानेसर, कुरुक्षेत्र शहर के उत्तर में स्थित है। मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान इसी स्थान पर पाण्डवों ने श्रीकृष्ण सहित महादेव की पूजा-अर्चना कर युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर सर्वप्रथम स्थाणु लिंग की स्थापना की। जिसके बाद लिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। देशभर में स्थाणु नाम का एक ही शिवलिंग है। स्थाणु की स्थापना के बाद ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किये गए थे। स्थाणु तीर्थ के नाम पर ही वर्तमान थानेसर नगर का नामकरण हुआ है। जिसे प्राचीन काल में स्थाणिश्वर कहा जाता था। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार यहां पर भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी और सरस्वती की पूजा-अर्चना के बाद स्थाणु तीर्थ की स्थापना की।महादेव मंदिर में वर्ष में दो बार शिवरात्री पर भव्य मेला लगता है। तीर्थ के संचालक महंत बन्सी पूरी कहते हैं कि भगवान शिव रुद्र रूप में चंचल थे। भगवान शिव ने अपनी चंचलता को दूर करने के लिए आराधना की। जिसके बाद वे स्थाणु हो गए। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा की 8वीं पीढ़ी में महाराजा वेन हुए। वेन को पृथु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बताते हैं कि महाराजा पृथु ने पिहोवा नगर बसाया था जिसे पृथुदक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।

मंदिर के संचालक रोशन पुरी जी कहते है कि थानेसर में ही भद्रकाली शक्तिपीठ है। देवी भागवत के अनुसार शक्तिपीठ का पुराना नाम सावित्री शक्ति पीठ है। यत्र सावित्रि देवी, तत्र स्थाणु भैरव अर्थात- जहां पर सावित्री देवी (भद्रकाली) शक्तिपीठ है। उसके भैरव स्थाणु महादेव ही हैं। अतः स्थाणु के पूजन के बिना भद्रकाली का पुजन अधूरा माना जाता है। वर्तमान में जो शिव मंदिर बना है। इसका जीर्णोधार मराठा सेनापत्ति सदाशिव राव भाहु ने लगभग 1750-55 ई. में करवाया था। मंदिर का गुंबद प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। गुंबद के अंदरूनी भाग में सुंदर भित्ती चित्रकारी है।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व कृष्णा सर्किट के अन्तर्गत महादेव मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग से ब्लाक बनवाया गया है। साथ ही परिसर में वाहन सुविधा के लिए पार्किंग बनवाई गई है।

मनोज चौहान

कोविड-19 महामारी के चलते पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

आईएएस अधिकारी सीएम विंडो के तहत शिकायतों के निपटान की प्रगति की निगरानी, विभिन्न विभागों की प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, केंद्रीय और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।

(द्वितीय अध्याय, श्लोक 47)

अर्थ- कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं... इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य-कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो।

श्रीमद्भगवद् गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। यह किसी जाति, धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का ग्रंथ है। यह मनुष्यों को कर्म का संदेश देता है। मनुष्य जीवन की चिंताओं, समस्याओं, अनेक तरह के तनावों से घिरा हुआ है, कई बार वह भटक जाता है, ऐसे में गीता मानव को क्रियाशीलता का संदेश देती है और जीवन जीने की कला सिखाती है।

संवाद ब्यूरो

कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर तट के नजदीक आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रतिवर्ष देश व विदेश के सैलानियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन इस वर्ष महामारी कोविड-19 के कारण आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को जहन में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन आनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया गया। देश व विदेश में बैठे लोगों ने अपने घरों में रहकर ही आनलाईन प्रणाली से महोत्सव के कार्यक्रमों का आनंद लिया। वेबिनार के माध्यम से भी श्रीमद्भगवद्गीता के महत्त्व के प्रकाश डाला गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की जानकारियों और कुरुक्षेत्र के महत्त्व पर प्रकाश डालने के लिए 48 कोस के 134 तीर्थों पर प्रशासन की तरफ से विशेष एलईडी वैन भेजी गई। इसके अलावा 48 कोस के तीर्थों के महत्त्व और इतिहास की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए पहली बार छोटी-छोटी वीडियो की आईटी टीम द्वारा साईट पर अपलोड की गई।

ऑनलाईन महोत्सव

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2020 के उद्घाटन अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित ''सतत् अस्तित्व और श्रीमद्भगवद्गीता दर्शन'' वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित कर हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का दिव्य संदेश निष्काम कर्म का एक ऐसा दर्शन है, जो राष्ट्र, समाज व प्राणी मात्र के कल्याण और उन्नति का आधार है। उन्होंने हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ से ही ऑनलाईन जुड़कर अपना वर्चुअल संबोधन दिया। मुख्य अतिथि के रूप मे बोलते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। आज पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इस प्रकार के महोत्सव हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं।

कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व के बुद्धिजीवियों व संस्कृतिवेताओं का जिज्ञासा-केंद्र बना। करीब डेढ़ दर्जन देशों के संस्कृति-ज्ञाता वहां गीता के श्लोक व मंत्रोच्चारण में किसी साधु-सन्यासी की तरह लीन दिखे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पुरुषोतमपुरा बाग में गीता यज्ञ के लिए पांच कुंड बनाए गए। इस महोत्सव में स्पेन, स्विटजरलैंड, इटली, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, इज़रायल, जापान, हालैंड, जर्मनी, फ्रांस सहित अन्य देशों से गीता प्रेमी पहुंचे हैं। इन प्रतिनिधियों का नेतृत्व स्वामी ब्रह्मानंद (डेविड) ने किया जो कि पिछले 40 सालों से पवित्र ग्रंथ गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इन विदेशी में लोगों सुबह ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग के हवन कुंड के पास बैठकर हिंदू परंपरा अनुसार श्लोकों और मंत्रों का उच्चारण किया तथा गीता यज्ञ में आहूति भी डाली।

स्वामी ब्रह्मानंद डेविड, जर्मनी से कैटरिना, स्वीटजरलैंड से लेतीजिया, न्यूयार्क से तस्लीन और फ्रांस से आए कृष ने कहा कि गीता उदगम स्थल को देखने के लिए काफी सालों से प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस वर्ष गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रयासों से उनका सपना साकार हो पाया है।

ऑनलाईन हुआ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव

उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2020 के सभी कार्यक्रमों का आयोजन आनलाईन प्रणाली के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। प्रशासन का प्रयास रहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश शहर तक ही नहीं, अपितु गांव-गांव और विदेशों तक भी पहुंचाया जाए। इस वर्ष प्रशासन की तरफ से ग्राम सचिवालयों, सीएससी सेंटरों पर भी आनलाईन प्रणाली से कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की गई और स्मार्ट फोन के माध्यम से भी अनेक लोगों ने महोत्सव के कार्यक्रमों को देखा।

'गीता की उपयोगिता'

श्रीमद्भगवद्गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने विषाद यानि डिप्रेशन को भी योग अर्थात आनंद तक पहुंचाया। जब महाभारत के युद्ध से पूर्व दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन विषादग्रस्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर उसे विषाद मुक्त करके योग तक पहुंचाया।

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज

श्रीमद्भगवद्गीता हर क्षेत्र के व्यक्ति को रास्ता दिखाने और समस्या का समाधान बताती है। भारतीय साहित्य पूरी दुनिया में प्रचलित है। ऋग्वेद लिखित में एकमात्र वेद है। दर्शन के समकालीन वेदों से पुराणों तक ऋग्वेद में आयुर्वेद पर चिंतन किया गया, जिसमें 24 तत्वों से शरीर मिलकर बनने के बारे में लिखा गया है।

डॉ. बलदेव धीमान, कुलपति, श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय

ऑनलाईन वीडियो में बताया कि एक बार जब स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने उन्हें गीता और चिकित्सा विषय पर बोलने के लिए कहा तो उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की, जिससे समझ में आया कि जब एक हृदय रोगी अपना ईलाज कराने के लिए हमारे पास आता है तो वह केवल बीमारी नहीं, बल्कि अपने सिर पर काफ़ी बोझ लेकर आता है। गीता पढ़ने के बाद जब मैंने उन मरीजों की बीमारी के साथ-साथ उसके परिवार, कार्यक्षेत्र और दूसरी समस्याओं को भी सुना तो मरीज को लगने लगा कि चिकित्सक ने न केवल उसकी बीमारी, बल्कि उसकी पीड़ा को भी समझ लिया है। इसके बाद मेरे खुद के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया है।

डा. नरेश त्रेहन, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता

कोरोना महामारी के बीच उनके पति आम बिडला भी श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरणा लेते रहे हैं वे भविष्य में भी जीओ गीता से जुड़ी रहेंगी और श्रीमद्भगवद्गीता को लोगों की प्रेरणा बनाएंगी।

डॉ. अमिता बिडला, स्त्री रोग विशेषज्ञ

धर्म के अनुसार कर्म करना ही श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश है। 2020 में आई कोरोना महामारी के दिनों में अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण कार्य किए। हर एक प्रश्न का उत्तर गीता में है। गीता नकारात्मक से सकारात्मक की खूबसूरत यात्रा है।

डा. मारकंडेय आहूजा, कुलपति, गुरुग्राम विश्वविद्यालय

पी सी मीणा, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com